>

Title: Need to fix a remunerative Minimum Support Price for cotton.

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): महोदया, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में कपास की फसल उत्पादित करने वाले किसानों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर हो रही है। आए दिन किसानों की आत्महत्या की घटनाएं घट रही हैं, किंतु कपास उत्पादक किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है।

भारत देश विश्व का लगभग 15 प्रतिशत कपास पैदा करता है जिसमें विदर्भ क्षेत्र का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है। देश का प्रमुख कपास उत्पादक प्रदेश होने के बावजूद यहां कि किसानों की हालत शोचनीय है। एक समय था जब विदर्भ का किसान कपास की फसल पर अपने परिवार की रोजी रोटी कमा लेता था किंतु पिछले कुछ वर्षों में कपास उत्पादक किसानों की परिस्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। कपास की लागत का खर्च और कपास चुनने वाले मजदूरों की कमी एवं बढ़ती मजदूरी के कारण कपास उत्पादक किसानों की लागत काफी बढ़ गई है। एक एकड़ कपास की लागत लगभग 12 हजार रूपये है लेकिन कपास का उचित मूल्य न मिलने के कारण आज कपास की फसल उगाना घाटे का सौदा बन गया है।

विदर्भ में सिंचाई की सुविधा न होने के कारण 90 फीसदी किसानों को कपास की फसल उगाना ही एकमात्र विकल्प है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष लगभग 360 लाख गांठे कपास उत्पादन होने का अनुमान है। किसान अपनी फसल को लेकर चिंतित है, क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई न्यूनतम मूल्य घोषित नहीं किया है। गत वर्ष कपास का निर्धारित मूल्य 3000 रूपये प्रति क्विंटल था और खुले बाजार में 7000 रूपये प्रति क्विंटल था। इसी कारण किसान सरकार से नाराज हैं और उनमें आक्रोश की भावना पनप रही है। किसान संगठनों और विदर्भ के राजनेताओं ने कपास उत्पादक किसानों की समस्या पर आवाज उठाई है और सरकार को कपास का समर्थन मूल्य 6000 रूपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह कपास उत्पादक किसानों की समस्या को जल्द से जल्द निपटाए और उन्हें 6000 रूपये प्रति क्विंटल कपास का उचित मूल्य दे और आए दिन हो रही किसानों की आत्महत्याओं को रोक लें।